

 सत्यमेव जयते	<b>राजस्थान राजपत्र</b> <b>विशेषांक</b>	<b>RAJASTHAN GAZETTE</b> <b>Extraordinary</b>
	<b>साधिकार प्रकाशित</b>	<b>Published by Authority</b>
	वैशाख 18, बुधवार, शाके 1946-मई 08, 2024 <i>Vaisakha 18, Wednesday, Saka 1946- May 08, 2024</i>	

**भाग-1(ख)**

**महत्वपूर्ण सरकारी आज़ायें।**  
**सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर**

**अधिसूचना**

**जयपुर, मार्च 19, 2023**

**(अन्तर्गत भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 (1))**

**संख्या 14718 :-**राजस्थान के राज्यपाल द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के तहत राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के प्रावधानुसार एवं राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.1(150)राज.-6/2016/02 दिनांक 27.01.2017 के निर्देशानुसार Consultancy services for Social Impact Assessment study for the purpose of land acquisition of Butati to Degana Road (Nimbari Chandwata-Butati- Bachhwari- Pandwala- Antroli Kallan- Antroli Khurd- Banwarla- Edwa- Pundlota- Mehrasi-Degana (Proposed Bypass in Butati, Pandwala & Edwa Village) in accordance with the Rajasthan as per RFCTLARR (Rajasthan Right to fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Rule.) के अधीन सार्वजनिक प्रयोजनार्थ तहसील सांजू एवं डेगाना, जिला-नागौर में निम्नानुसार प्रभावित गांवों में भूमि अर्जन किया जाना प्रस्तावित है।

क्र.सं.	जिला	तहसील	गांव	सक्षम प्राधिकारी एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी
1	नागौर	सांजू	(1) बूटाटी (2) पण्डवाला	उपखण्ड अधिकारी, डेगाना
2	नागौर	डेगाना	(1) ईडवा	उपखण्ड अधिकारी, डेगाना

यह अधिसूचना जारी कर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 की उप-धारा (1) एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2016 के प्रावधानों के अनुसरण में निम्न सूची अनुसार प्रभावित क्षेत्र में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन हेतु संबंधित ग्राम पंचायत, नगरपालिका, नगर निगम या अन्य कोई स्थानीय निकाय से सम्पर्क करने एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2016 के नियम 6(8) की पालना सुनिश्चित करने हेतु अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड डेगाना जिला नागौर को अधिकृत किया जाता है।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4(6) के अन्तर्गत **भूमि अवाप्ति अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी डेगाना जिला नागौर** संबंधित भूमि अवाप्ति अधिकारी होंगे।

अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड डेगाना जिला नागौर द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भूअर्जन से प्रभावित गाँवों में सामाजिक समाघात निर्धारण राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2016 के प्रावधानुसार किया जायेगा। सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया निम्नानुसार होगा:-

1. संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों का विवरण तैयार कर सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रारूप रिपोर्ट तैयार की जावेगी।
2. प्रारूप रिपोर्ट की प्रति प्रभावित गाँवों में समुचित स्थान पर प्रदर्शित की जावेगी। तत्पश्चात् प्रभावित गाँवों में पर्याप्त प्रचार-प्रसार के उपरान्त जनसुनवाई की जावेगी, जिसका कार्यवाही विवरण समुचित रूप से रिकॉर्ड किया जायेगा।
3. जन-सुनवाई के दौरान आए सुझावों/आपत्तियों के समुचित समाघात को शामिल कर सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना रिपोर्ट तैयार की जावेगी।
4. सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया प्रभावित गाँवों में संबंधित पंचायत/नगरपालिका के परामर्श से की जावेगी।
5. सामाजिक समाघात मूल्यांकन के दौरान किसी भी प्रकार के बल प्रयोग या धमकी का प्रयत्न इस कवायद को अछूत और शून्य बना देगा।
6. सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया को इस अधिसूचना की तिथि से प्रारंभ किया जायेगा एवं अधिकतम 8 माह की अवधि में सम्पूर्ण करवाया जाना आवश्यक है।

**सम्पर्क सूत्र:-**

**सामाजिक समाघात निर्धारण ईकाई**

**कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता**

सा.नि.वि. खण्ड डेगाना जिला नागौर

**सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी**

**सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड डेगाना जिला नागौर**

शंकरलाल जाट, मोबाईल : 9414769922

**अधिशाषी अभियन्ता,**

**सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड डेगाना जिला नागौर**

सुनील गुप्ता,

संयुक्त सचिव (पथ),

सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान, जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।